



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 21 जून, 2021/31 ज्येष्ठ, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या: 1/2021-राज्य कर

शिमला-2, 11 जून, 2021

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर और हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम जनवरी 1, 2021 से प्रवृत्त होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 59 में उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

“(6) इस नियम में किसी भी बात के होते हुए भी,—

- (क) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने पिछले दो महीने के लिए जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है तो उसे धारा 37 के अधीन जीएसटीआर-1 में अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।
- (ख) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसे धारा 39 की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन हर तिमाही का रिटर्न भरना जरूरी हो, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर-1 या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।
- (ग) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिस पर नियम 86ख के अधीन यह प्रतिबंध हो कि 99 प्रतिशत से अधिक देय कर का भुगतान करने के लिए वह अपने इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं कर सकता है, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर-1 या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—

(जगदीश चन्द्र शर्मा),

अति0 मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021, dated 11th June, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 1/2021-State Tax

Shimla-2, the 11th June, 2021

No. EXN-F(10)-4/2021.—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (First Amendment) Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force with effect from 1st January, 2021.

2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter in this notification referred to as the said rules), in rule 59, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(6) Notwithstanding anything contained in this rule,—

- (a) a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in FORM GSTR-1, if he has not furnished the return in FORM GSTR-3B for preceding two month,
- (b) a registered person, required to furnish return for every quarter under the proviso to sub-section (1) of Section 39, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in FORM GSTR- 3B for preceding tax period;
- (c) a registered person, who is restricted from using the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards tax in excess of ninety-nine percent of such tax liability under rule 86B, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in FORM GSTR-3B for preceding tax period.”.

By order,

Sd/-
(JAGDISH CHANDER SHARMA),
Addl. Chief Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या: 7/2021—राज्य कर

शिमला-2, 14 जून, 2021

संख्या ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—4/2021.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 164 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में, नियम 26 के उप-नियम (1) में, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह भी किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 27 अप्रैल, 2021 से 31 मई, 2021 तक की अवधि के दौरान, धारा 39 के तहत प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी को एवं धारा 37 के तहत प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किये जाने वाले जावक प्रदायों के ब्यौरे को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमति है।”

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/—

(जगदीश चन्द्र शर्मा),

अति0 मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021, dated 14th June, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 7/2021-State Tax

Shimla-2, the 14th June, 2021

No. EXN-F(10)-4/2021.—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017(10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. (1) Theses Rules may be called the Himachal Pradesh Good and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 26 in sub- rule (1), after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“ Provided also that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall, during the period from the 27th day of April, 2021 to the 31st day of May, 2021, also be allowed to furnish the return under section 39 in FORM GST-3B and the details of outward supplies under section 37 in FORM GSTR-1 or using invoice furnishing facility, verified through electronic verification code (EVC).”

By order,

Sd/-

(JAGDISH CHANDER SHARMA),

Addl. Chief Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या: 8/2021-राज्य कर

शिमला-2, 14 जून, 2021

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 50 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर, दिनांक 30 जून, 2017 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017, दिनांक 30 जून 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:—

(i) उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक में, निम्नलिखित को तालिका में क्र० सं० 3 के बाद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--|--|-----------------------------------|
| 4 | करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो | नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, उसके बाद 18 प्रतिशत | मार्च 2021, अप्रैल, 2021 |
| 5 | करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं | नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, उसके बाद 18 प्रतिशत | मार्च 2021, अप्रैल, 2021 |
| 6 | करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं | नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, उसके बाद 18 प्रतिशत | मार्च 2021, अप्रैल, 2021 |
| 7 | करदाता, जो धारा 39 की उप-धारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं | नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, उसके बाद 18 प्रतिशत | तिमाही जो मार्च 2021, अप्रैल 2021 |

(2) इस अधिसूचना को अप्रैल, 2021 के 18वें दिन से लागू माना जाएगा।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/—

(जगदीश चन्द्र शर्मा),

अति० मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021, dated 14th June, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 8/2021-State Tax

Shimla-2, the 14th June, 2021

No. EXN-F(10)-4/2021.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017(10 of 2017), read with Section 148 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 13/2017-State Tax, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* number EXN-F(10)-14/2017, dated 30-06-2017, namely:—

(i) In the said notification, in the first paragraph, in the first proviso, in the Table after Sr. No. 3, the following shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--|---|-------------------------------|
| “4. | Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year | 9 percent for the first 15 days from the due date and 18 percent thereafter | March, 2021, April, 2021 |
| 5. | Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of Section 39 | Nil for the first 15 days from the due date, 9 percent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter | March, 2021, April, 2021 |
| 6. | Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of Section 39 | Nil for the first 15 days from the due date, 9 percent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter | March, 2021, April, 2021 |
| 7. | Taxpayers who are liable to furnish the return as specified under sub-section (2) of Section 39 | Nil for the first 15 days from the due date, 9 percent for the next 15 days, and 18 percent thereafter | Quarter ending March, 2021.”. |

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 18th day of April, 2021.

By order,
Sd/-
(JAGDISH CHANDER SHARMA),
Addl. Chief Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या: 9/2021-राज्य कर

शिमला-2, 14 जून, 2021

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, अधिसूचना संख्या 76/2018-राज्य कर दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018, दिनांक 1 जनवरी, 2019 के तहत प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सातवें परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो निम्न तालिका के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट किए गए हैं, जो प्ररूप जीएसटीआर-3ख विवरणी को नियत तारीख तक प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं, निम्न तालिका के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देय विलंब फीस को निम्न तालिका के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा के लिए अधिकृत किया जाता है, अर्थात्:—

तालिका

| क्र० सं० | रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग | कर अवधि | सीमा जिसके लिये विलंब फीस अधिकृत किया गया |
|----------|--|-------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो | मार्च 2021, अप्रैल 2021 | विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले पंद्रह दिन तक |
| 2 | करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं | मार्च 2021, अप्रैल 2021 | विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले तीस दिन तक |
| 3 | करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं | जनवरी – मार्च 2021 | विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले तीस दिन तक |

(2) इस अधिसूचना को अप्रैल 2021 के 20वें दिन से लागू माना जाएगा।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/—

(जगदीश चन्द्र शर्मा),

अति० मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021, dated 14th June, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 9/2021-State Tax

Shimla-2, the 14th June, 2021

No. EXN-F(10)-4/2021.—In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017(10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 76/2018-State Tax dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* number EXN-F(10)-33/2018, dated 01-01-2019, namely:—

In the said notification, after the seventh proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that the amount of late fee payable under section 47 shall stand waived for the period as specified in column (4) of the Table given below, for the tax period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the returns in FORM GSTR-3B by the due date, namely:—

TABLE

| Sl. No. | Class of registered persons | Tax period | Period for which late fee waived |
|---------|--|-------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| “1. | Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year | March, 2021, April 2021 | Fifteen days from the due date of furnishing return |
| 2. | Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of Section 39 | March 2021, April 2021 | Thirty days from the due date of furnishing return |
| 3. | Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of Section 39 | January-March 2021 | Thirty days from the due date of furnishing return.”. |

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of April, 2021.

By order,

Sd/-
(JAGDISH CHANDER SHARMA),
Addl. Chief Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या: 10/2021-राज्य कर

शिमला-2, 14 जून, 2021

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 148 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, अधिसूचना संख्या 21/2019-राज्य कर दिनांक 30 मई, 2019 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2019, दिनांक 30 जून 2019, के तहत प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के तीसरे अनुच्छेद में पहले परंतुक के उपरान्त, निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह भी कि उक्त व्यक्ति 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-04 में विवरणी मई 2021 के 31 वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे।”।

2. यह अधिसूचना अप्रैल 2021 के 30 वें दिन से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/—
(जगदीश चन्द्र शर्मा),
अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021 dated 14th June, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 10/2021-State Tax

Shimla-2, the 14th June, 2021

No. EXN-F(10)-4/2021.—In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017(10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification No. 21/2019-State Tax, dated the 30th May, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10)-4/2019, dated 03-06-2019, namely:—

In the said notification, in the third paragraph, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that the said persons shall furnish the return in FORM GSTR-4 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, for the financial year ending 31st March, 2021, upto the 31st day of May, 2021.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 30th day of April, 2021.

By order,

Sd/-

(JAGDISH CHANDER SHARMA),
Addl. Chief Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या: 11 / 2021—राज्य कर

शिमला-2, 14 जून, 2021

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4 / 2021.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 168 और हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 45 के उप-नियम (3), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, 1 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान किसी फुटकर काम करने वाले कर्मकार को पारेषित मालों या किसी फुटकर काम करने वाले कर्मकार से वापस आये मालों के संबंध में, प्ररूप जीएसटी आईटीसी-04 में प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा करने की समय सीमा को एतद्वारा मई 2021 के 31वें दिन तक बढ़ाते हैं।

2. यह अधिसूचना अप्रैल 2021 के 25 वें दिन से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—

(जगदीश चन्द्र शर्मा),

अति० मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021 dated 14th June, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 11/2021-State Tax

Shimla-2, the 14th June, 2021

No. EXN-F(10)-4/2021.—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017(10 of 2017) and sub-rule (3) of rule 45 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor of Himachal Pradesh, hereby extends the time period upto the 31st day of May, 2021, for furnishing the declaration in FORM GST ITC-04, in respect of goods dispatched to a job worker or received from a job worker, during the period from 1st January, 2021 to 31st March, 2021.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 25th day of April, 2021.

By order,
Sd/-
(JAGDISH CHANDER SHARMA),
Addl. Chief Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या: 12/2021—राज्य कर

शिमला-2, 14 जून, 2021

संख्या ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—4/2021.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, अधिसूचना संख्या 83/2020—राज्य कर दिनांक 14 दिसंबर, 2020 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—14/2020 दिनांक 18 दिसंबर 2020, के तहत प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में परंतुक के बाद, निम्न परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

“परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं, माह अप्रैल 2021 की कर अवधि के लिए, उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्ति के ब्यौरों को प्रस्तुत करने की समय सीमा को उक्त कर अवधि के उत्तरवर्ती माह के छब्बीसवें दिन तक बढ़ाया जाता है।”

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—
(जगदीश चन्द्र शर्मा),
अति० मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021 dated 14th June, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 12/2021-State Tax

Shimla-2, the 14th June, 2021

No. EXN-F(10)-4/2021.—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017(10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh on the recommendations of the Council, is pleased to make the following amendment in the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 83/2020-State Tax, dated the 14th December, 2020, published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* number EXM-F(10)-14/2020, dated 18-12-2020, namely:—

In the said notification, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided further that the time limit for furnishing the details of outward supplies in FORM GSTR-1 of the said rules for the registered persons required to furnish return under sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the tax period April, 2021, shall be extended till the twenty-sixth day of the month succeeding the said tax period.”.

By order,
Sd/-
(JAGDISH CHANDER SHARMA),
Addl. Chief Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या: 13/2021—राज्य कर

शिमला-2, 15 जून, 2021

संख्या ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—4/2021.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 164 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में.—

(i) नियम 36 के उपनियम (4) में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह भी कि उक्त शर्त अप्रैल और मई, 2021 की अवधि के लिए संचयी रूप से लागू होगी और मई, 2021 की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की विवरणी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी।”;

3. नियम 59 के उपनियम (2) में, निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माह अप्रैल 2021 के लिए, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए उक्त ब्यौरों को मई 2021 के पहले दिन से 28वें दिन तक प्रस्तुत कर सकता है। ”

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/—

(जगदीश चन्द्र शर्मा),

अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021 dated 15th June, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 13/2021-State Tax

Shimla-2, the 15th June, 2021

No. EXN-F(10)-4/2021.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017(10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017,—

(i) in sub-rule (4) of rule 36, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that such condition shall apply cumulatively for the period April and May, 2021 and the return in FORM GSTR-3B for the tax period May, 2021 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above.”;

(ii) in sub-rule (2) of rule 59, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that a registered person may furnish such details, for the month of April, 2021, using IFF from the 1st day of May, 2021 till the 28th day of May, 2021.”.

By order,
Sd/-
(JAGDISH CHANDER SHARMA),
Addl. Chief Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या: 14/2021-राज्य कर

शिमला-2, 15 जून, 2021

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 168 क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, भारत में कई हिस्सों में महामारी कोविड-19 के चलते यह अधिसूचित करते हैं कि—

(i) जहां, किसी भी प्राधिकरण द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी भी समय सीमा को, जो अप्रैल, 2021 के 15 वें दिन से मई, 2021 के 30वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरी करना या उसका अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं किया गया है, तो, निम्न उद्देश्यों सहित के लिए, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय-सीमा मई, 2021 के 31वें दिन तक बढ़ा दी जाएगी—

- (क) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन किसी भी प्राधिकरण, आयोग या न्यायाधिकरण द्वारा, किसी कार्रवाई को पूरी करना, किसी भी आदेश पारित करने, किसी नोटिस को जारी करना, सूचना, अधिसूचना, संस्वीकृति या अनुमोदन या इस तरह की अन्य कार्रवाई, जो भी नाम से हो; या
- (ख) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के तहत, कोई अपील दाखिल करना, कोई भी रिपोर्ट, दस्तावेज, विवरणी, ब्यान, या ऐसे अन्य रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना, जो भी नाम से पुकारा जाता है; लेकिन, समय का ऐसा विस्तार उक्त अधिनियम के निम्न प्रावधानों के अनुपालन के लिए लागू नहीं होगा, जैसा कि नीचे वर्णित है—

(क) अध्याय प्टय

(ख) धारा 10 की उपधारा (3), धारा 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;

(ग) धारा 39, परंतु, उपधारा (3), (4) और (5) को छोड़ कर;

(घ) धारा 68, जहां तक ई-वे बिल का संबंध है; तथा

(ङ) ऊपर वर्णित अध्याय और धारा के तहत बनाए गए नियम;

परंतु जहां, हिमाचल प्रदेश वस्तु और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 9 के तहत निर्दिष्ट, या निर्धारित या अधिसूचित किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने की कोई समय सीमा, जो मई, 2021 के पहले दिन से मई, 2021 के इकत्तीसवें दिन तक की अवधि के दौरान आती है, और जहां ऐसी कार्रवाई ऐसे समय के भीतर पूरी नहीं की गई है, तो, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की समय सीमा, जून, 2021 के पंद्रहवें दिन तक विस्तार किया जाता है।

(ii) ऐसे मामलों में जहां रिफंड के दावे को, पूर्ण या भाग में, अस्वीकार करने के लिए नोटिस जारी किया गया है, और जहां आदेश जारी करने की समय सीमा धारा 54 उप धारा (7) के साथ पठित उपधारा (5) के प्रावधानों के संदर्भ में अप्रैल, 2021 के पंद्रहवें दिन से मई, 2021 के तीसवें दिन तक की अवधि के दौरान आती है, ऐसे मामलों में उक्त आदेश जारी करने की समय सीमा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से नोटिस का जवाब प्राप्ति के पंद्रह दिन बाद या मई, 2021 के इकत्तीसवें दिन, जो भी बाद में हो, तक बढ़ा दिया जाता है।

2. यह अधिसूचना अप्रैल, 2021 के 15वें दिन से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/—

(जगदीश चन्द्र शर्मा),

अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021, dated 15th June, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 14/2021-State Tax

Shimla-2, the 15th June, 2021

No. EXN-F(10)-4/2021.—In exercise of the powers conferred by section 168A of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017(10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and section 21 of Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), in view of the spread of pandemic COVID-19 across many parts of India, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, hereby notifies, as under:—

- (i) where, any time limit for completion or compliance of any action, by any authority or by any person, has been specified in, or prescribed or notified under the said Act, which falls during the period from the 15th day of April, 2021 to the 30th day of May, 2021, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action, shall be extended upto the 31st day of May, 2021, including for the purposes of—
 - (a) completion of any proceeding or passing of any order or issuance of any notice, intimation, notification, sanction or approval or such other action, by whatever name called, by any authority, commission or tribunal, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above; or

- (b) filing of any appeal, reply or application or furnishing of any report, document, return, statement or such other record, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above;

but, such extension of time shall not be applicable for the compliances of the following provisions of the said Act, namely:—

- (a) Chapter IV;
- (b) sub-section (3) of section 10, sections 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;
- (c) section 39, except sub-section (3), (4) and (5);
- (d) section 68, in so far as e-way bill is concerned; and
- (e) rules made under the provisions specified at clause (a) to (d) above :

Provided that where, any time limit for completion of any action, by any authority or by any person, specified in, or prescribed or notified under rule 9 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, falls during the period from the 1st day of May, 2021 to the 31st day of May, 2021, and where completion of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion of such action, shall be extended upto the 15th day of June, 2021;

- (ii) in cases where a notice has been issued for rejection of refund claim, in full or in part and where the time limit for issuance of order in terms of the provisions of sub-section (5), read with sub-section (7) of section 54 of the said Act falls during the period from the 15th day of April, 2021 to the 30th day of May, 2021, in such cases the time limit for issuance of the said order shall be extended to fifteen days after the receipt of reply to the notice from the registered person or the 31st day of May, 2021, whichever is later.

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of April, 2021.

By order,
Sd/-
(JAGDISH CHANDER SHARMA),
Addl. Chief Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या: 15/2021—राज्य कर

शिमला-2, 16 जून, 2021

संख्या ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—4/2021.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में,—

(i) नियम 23 के उपनियम (1) में, “रजिस्ट्रीकरण के रहकरण के आदेश की तामील की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर” शब्दों के पश्चात्, “या ऐसी अवधि के भीतर, जो धारा 30 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन उपबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त या आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए,” शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) नियम 90 में,—

(क) उपनियम (3) में निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

“परंतु यह कि कमियों को सुधारने के बाद आवेदक द्वारा दायर किए गए नए प्रतिदाय के दावे के संबंध में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में प्रतिदाय के दावे को दायर करने की तारीख से समुचित अधिकारी द्वारा प्ररूप जीएसटी आरएफडी-03 में कमियों को संसूचित करने की तारीख तक की, समय अवधि को, धारा 54 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट दो साल की समय सीमा से बाहर रखा जाएगा।

(ख) उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः—

“(5) आवेदक, किसी प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में दायर किए गए प्रतिदाय के आवेदन के संबंध में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-04 में अनंतिम प्रतिदाय मंजूरी आदेश या प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में अंतिम स्वीकृत प्रतिदाय आदेश या प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 संदाय आदेश या प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07 में प्रतिदाय रोकने के लिए आदेश या प्ररूप जीएसटी आरएफडी-08 में नोटिस, के जारी किए जाने से पूर्व किसी भी समय, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 डब्ल्यू में आवेदन दायर करके प्रतिदाय के लिए आवेदन को वापस ले सकेगा।

(6) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में प्रतिदाय के लिए आवेदन करते समय, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक उधार खाता या इलेक्ट्रॉनिक नगद खाता से आवेदक द्वारा विकलित कोई रकम प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 डब्ल्यू में प्रतिदाय की वापसी के आवेदन को प्रस्तुत करने पर उस खाते में वापस जमा की जाएगी जिससे ऐसा विकलन किया गया था।”;

(iii) नियम 92 में,—

(क) उपनियम (1) में परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ख) उपनियम (2) में,—

(i) “भाग ख”, शब्द और अक्षर के स्थान पर, “भाग क” शब्द और अक्षर रखा जाएगा;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

“परंतु जहां समुचित अधिकारी या आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिदाय इससे अधिक रोके जाने हेतु दायी नहीं है, वहां वह प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07 के भाग-ख में रोके गए प्रतिदाय को जारी किए जाने का आदेश पारित कर सकेगा।”;

(iv) नियम, 96 में,—

- (क) नियम 6 में, "भाग ख", शब्द और अक्षर के स्थान पर, "भाग क" शब्द और अक्षर रखा जाएगा;
- (ख) उपनियम (7) में, "प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में आदेश पारित करने के पश्चात्", शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07 के भाग-ख में रोके गए प्रतिदाय को जारी करने के लिए किसी आदेश को पारित करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में कोई आदेश पारित करने के पश्चात्" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (v) उक्त नियम के प्ररूप जीएसटी आरईजी-21 में, "आरईजी के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश" उपशीर्ष के अधीन, पहले बुलेट बिंदु में, "आरईजी के रद्दकरण के आदेश की तारीख से तीस दिन में" शब्दों के पश्चात्, "या ऐसी अवधि के भीतर, जो धारा 30 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन उपबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त या आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए," शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
- (vi) नियम 138ई में, "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में चाहे वो प्रदायकर्ता हो या प्राप्तिकर्ता हो" शब्दों को "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के द्वारा माल के किसी भी जावक संचलन के संबंध में" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (vii) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थातः—

प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07

(नियम 92(2) और नियम 96(6) देखें)

संदर्भ सं.

तारीख:

सेवा में

.....(जीएसटीआईएन/विशिष्ट पहचान सं./अस्थायी पहचान-पत्र)

.....(नाम)

.....(पता)

.....(एआरएन)

भाग-क
प्रतिदाय रोकने के लिए आदेश

उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट एआरएन के संबंध में आयकरदाता को संदेय प्रतिदाय हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उपधारा (10) / उपधारा (11) के उपबंधों के अनुसार रोका जाता है। रोके जाने के लिए कारण निम्न प्रकार है:

| क्र. सं. | विशिष्टियां | |
|----------|---------------------------|-----------------|
| 1. | एआरएन | |
| 2. | आरएफडी-01 में दावाकृत रकम | <ऑटो पोपुलेटेड> |

| | | |
|----|--|---|
| 3. | आरएफडी-06 में अग्राह्य रकम | <ऑटो पोपुलेटेड> |
| 4. | आरएफडी-06 में समायोजित रकम | <ऑटो पोपुलेटेड> |
| 5. | रोकी गई रकम | |
| 6. | रोके जाने के लिए कारण (एक से अधिक कारण का चयन किया जा सकता है) | <ul style="list-style-type: none"> • वसूलनीय देय, जो संदत्त नहीं किए • धारा 54 की उपधारा (11) को ध्यान में रखते हुए, • गंभीर प्रकृति के कपट(टों) के कारण • अन्य, (विनिर्दिष्ट करें) |
| 7. | कारणों का वर्णन | (पांच सौ अक्षरों तक, विस्तृत कारणों के लिए पृथक फाइल संलग्न की जा सकती है) |
| 8. | व्यक्तिगत सुनवाई का रिकॉर्ड | (पांच सौ अक्षरों तक, विस्तृत कारणों के लिए पृथक फाइल संलग्न की जा सकती है) |

भाग -ख

रोके गए प्रतिदाय को जारी करने का आदेश

यह आपके प्रतिदाय आवेदन <एआरएन> दिनांक <दिनांक> के संदर्भ में है, जिसके विरुद्ध आदेश <आरएफडी-06 आदेश संख्या> दिनांक <दिनांक> द्वारा स्वीकृत संदेय प्रतिदाय की राशि के भुगतान को इस कार्यालय के आदेश <आदेश संख्या> दिनांक <दिनांक> द्वारा रोक दिया गया था। अब मैंने अपनी संतुष्टि में यह पाया है कि प्रतिदाय की रकम को रोके जाने की शर्त अब अस्तित्व में नहीं है और इसलिए, रोके गए प्रतिदाय की राशि को निम्नानुसार जारी किए की अनुमति दी जाती है:

| क्र. सं. | विशिष्टियां | |
|----------|----------------------------|-----------------|
| 1. | एआरएन | |
| 2. | आरएफडी-01 में दावाकृत रकम | <ऑटो पोपुलेटेड> |
| 3. | आरएफडी-06 में अग्राह्य रकम | <ऑटो पोपुलेटेड> |
| 4. | आरएफडी-06 में समायोजित रकम | <ऑटो पोपुलेटेड> |
| 5. | रोकी गई रकम | <ऑटो पोपुलेटेड> |
| 6. | जरी की गई रकम | |
| 7. | संदत्त की जाने वाली रकम | |

तारीख :

हस्ताक्षर

(डीएससी) :

स्थान :

नाम :

पदनाम :

कार्यालय पता : "य

(viii) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01ख के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

“प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01डब्ल्यू
नियम 90(5) देखिए ,
प्रतिदाय आवेदन की वापसी हेतु आवेदन

1. एआरएन :

2. माल और सेवा कर पहचान सं. :

3. कारबार का नाम (विधिक) :
4. व्यापार नाम, यदि कोई हो :
5. कर अवधि :
6. दावा किए गए प्रतिदाय की रकम :
7. प्रतिदाय दावा वापस लेने के लिए आधार :
 - i. प्रतिदाय आवेदन गलती से फाइल किया गया है
 - ii. प्रतिदाय आवेदन गलत प्रवर्ग के अधीन फाइल किया गया है
 - iii. प्रतिदाय आवेदन में गलत ब्यौरे उल्लिखित हैं
 - iv. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
8. मैं/हम (आयकरदाता का नाम) सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/करते हैं और यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि इसमें दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

तारीख :

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

प्रास्थिति : "।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
जगदीश चन्द्र शर्मा,
अति० मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021, dated 16th June, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 15/2021-State Tax

Shimla-2, the 16th June, 2021

No. EXN-F(10)-4/2021.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017(10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017,—

- (i) in rule 23, in sub-rule (1), after the words “date of the service of the order of cancellation of registration”, the words and figures “or within such time period as extended by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner or the

Commissioner, as the case may be, in exercise of the powers provided under the proviso to sub-section (1) of section 30,” shall be inserted;

- (ii) in rule 90, - (a) in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted,—

“Provided that the time period, from the date of filing of the refund claim in FORM GST RFD-01 till the date of communication of the deficiencies in FORM GST RFD-03 by the proper officer, shall be excluded from the period of two years as specified under sub-section (1) of Section 54, in respect of any such fresh refund claim filed by the applicant after rectification of the deficiencies.”;

- (b) after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

“(5) The applicant may, at any time before issuance of provisional refund sanction order in FORM GST RFD-04 or final refund sanction order in FORM GST RFD-06 or payment order in FORM GST RFD-05 or refund withhold order in FORM GST RFD-07 or notice in FORM GST RFD-08, in respect of any refund application filed in FORM GST RFD-01, withdraw the said application for refund by filing an application in FORM GST RFD-01W.

(6) On submission of application for withdrawal of refund in FORM GST RFD-01W, any amount debited by the applicant from electronic credit ledger or electronic cash ledger, as the case may be, while filing application for refund in FORM GST RFD-01, shall be credited back to the ledger from which such debit was made.”;

- (iii) in rule 92,—

- (a) in sub-rule (1), the proviso shall be omitted;

- (b) in sub-rule (2),—

- (i) for the word and letter “Part B”, the word and letter “Part A” shall be substituted;

- (ii) the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that where the proper officer or the Commissioner is satisfied that the refund is no longer liable to be withheld, he may pass an order for release of withheld refund in Part B of FORM GST RFD- 07.”;

- (iv) in rule 96,—

- (a) in sub-rule (6), for the word and letter “Part B”, the word and letter “Part A” shall be substituted;

- (b) in sub-rule (7), for the words, letters and figures, “after passing an order in FORM GST RFD-06”, the words, letters and figures, “by passing an order in FORM GST RFD- 06 after passing an order for release of withheld refund in Part B of FORM GST RFD- 07” shall be substituted;

- (v) in FORM GST REG-21, under the sub-heading “Instructions for submission of application for revocation of cancellation of registration”, in the first bullet point

“after the words “date of service of the order of cancellation of registration”, the words and figures “or within such time period as extended by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner or Commissioner, as the case may be, in exercise of the powers provided under proviso to sub-section (1) of section 30,” shall be inserted;

(vi) in rule 138E, for the words “in respect of a registered person, whether as a supplier or a recipient, who, —” the words “in respect of any outward movement of goods of a registered person, who, —” shall be substituted.

(vii) for FORM GST RFD-07, the following FORM shall be substituted, namely:—

“FORM GST RFD-07
[See rules 92(2) & 96(6)]

Reference No.

Date:

To

_____(GSTIN/UIN/Temp. ID)

_____(Name)

_____(Address)

_____ (ARN)

Part-A

Order for withholding the refund

Refund payable to the taxpayer with respect to ARN specified above are hereby withheld in accordance with the provisions of sub-section (10)/ (11) of section 54 of the HPGST Act, 2017. The reasons for withholding are given as under:

| S. No. | Particulars | |
|--------|--|--|
| 1. | ARN | |
| 2. | Amount Claimed in RFD-01 | <Auto-populated> |
| 3. | Amount Inadmissible in RFD-06 | <Auto-populated> |
| 4. | Amount Adjusted in RFD-06 | <Auto-populated> |
| 5. | Amount Withheld | |
| 6. | Reasons for withholding (More than one reason can be selected) | <ul style="list-style-type: none"> • Recoverable dues not paid • In view of sub-section 11 of Section 54 • On account of fraud (s) of serious nature • Others, (specify) |
| 7. | Description of the reasons | (Up to 500 characters, separate file can be attached for detailed reasons) |
| 8. | 8 Record of Personal Hearing | (Up to 500 characters, separate file can be attached for detailed records) |

Part-B

Order for release of withheld refund

This has reference to your refund application <ARN> dated <date> against which the payment of refund amount sanctioned *vide* order <RFD-06 order No> dated <date> was withheld by this office order <Order Reference No> dated <date> . It has been now found to my satisfaction that the conditions for withholding of refund no longer exist and therefore, the refund amount withheld is hereby allowed to be released as given under:

| S. No. | Particulars | |
|--------|-------------------------------|------------------|
| 1. | ARN | |
| 2. | Amount Claimed in RFD-01 | <Auto-populated> |
| 3. | Amount Inadmissible in RFD-06 | <Auto-populated> |
| 4. | Amount Adjusted in RFD-06 | <Auto-populated> |
| 5. | Amount Withheld with RFD-07 A | <Auto-populated> |
| 6. | Amount Released | |
| 7. | Amount to be paid | |

Dated:

Signature (DSC):

Place:

Name:

Designation:

Office Address: ”;

(viii) after FORM GST RFD-01 B, the following FORM shall be inserted, namely:—

“FORM GST RFD-01 W
[Refer Rule 90(5)]
Application for Withdrawal of Refund Application

1. ARN:
2. GSTIN:
3. Name of Business (Legal):
4. Trade Name, if any:
5. Tax Period:
6. Amount of Refund Claimed:
7. Grounds for Withdrawing Refund Claim:
 - (i) Filed the refund application by mistake
 - (ii) Filed Refund Application under wrong category
 - (iii) Wrong details mentioned in the refund application
 - (iv) Others (Please Specify)

8. Declaration: I/We hereby solemnly affirm and declare that the information given herein is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place:

Signature of Authorised Signatory

Date:

Name Designation/ Status".

By order,

Sd/-

(JAGDISH CHANDER SHARMA),

Addl. Chief Secretary (E&T).

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Shimla- 4, the 17th June, 2021

No. VS/Estt./6-62/81-II.—The Hon'ble Speaker, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, is pleased to order the promotion of following Superintendent Grade-II of H.P. Vidhan Sabha to the posts of Section Officer in the pay scale of ₹15600-39100+5400/- GP on regular basis with immediate effect:—

- (i) Smt. Naina Kotvi
- (ii) Sh. Jeevan Singh
- (iii) Sh. Dharam Pal
- (iv) Smt. Shakuntla Soni

2. On promotion they will remain on probation for a period of two years reckoned from the date of issue of these orders.

3. They will be entitled to exercise option for fixation of pay within a period of one month from the issue of these orders under provisions of F.R. 22 and instructions contained in Department of Finance, Govt. of HP Office memorandum No. Fin (PER)B(7)-1/2009 dated 19-09-2009.

4. On promotion, the seniority position of incumbent figuring at Sl. No. (iv) shall strictly be in accordance with instructions contained in Department of Personnel, Govt. of H.P. letter No. PER(AP)C-F(1)-1/95, dated 27th May, 1996.

5. They will join on promotion within 15 days from the date of issue of these orders failing which the promotion orders shall deemed to be withdrawn automatically. No specific orders with reference to withdrawal of promotions will be issued separately.

Sd/-

Secretary,

H.P. Vidhan Sabha.

BAR COUNCIL OF HIMACHAL PRADESH
High Court Complex, Ravenswood, Shimla-171001

NOTIFICATION

Dated, 20th June, 2021

No. BCHP/Election-20-06-2021/2021/493-582.—It is hereby notified under Section 3 (3) of the Advocates Act, 1961 read with Rules 3 and 4 of the Bar Council of Himachal (Constitution and conduct of Business) Rules 1999, the following has been elected as Chairman of the Bar Council of Himachal Pradesh in its meeting held on 20th June, 2021.

1. Shri Ajay Kochhar, : Chairman
Advocate,
H.P. High Court.

Sd/-
(KRISHNA THAKUR),
Returning Officer.

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th June, 2021

No. EDN-A-Ka(1)-16/2016.—The Governor Himachal Pradesh is pleased to order to take over Shri Sarswati Sanskrit College Dangar, Teh. Ghumarwin, Distt. Bilaspur with immediate effect and rename it as Government Sanskrit College, Dangar, Distt. Bilaspur, H.P.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that Principal, Government Degree College, Ghumarwin, Distt. Bilaspur shall hold the additional charge of the post of Principal of newly taken over College i.e. Government Sanskrit College, Dangar, Distt. Bilaspur H.P. in addition to his present duties, without any extra remuneration, till further orders.

The concerned Principal is directed to take over the assigned additional charge immediately and take all appropriate steps to ensure smooth functioning of newly taken over Government Sanskrit College Dangar.

By order,
Sd/-
(RAJEEV SHARMA),
Secretary (Education).

